क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 336, शनिवार, 05 जनवरी, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

सीबीआई ने रिश्वत के मामले में आयकर अधिकारी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। सीबीआई ने आयकर रिटर्न नहीं भरने वाले एक व्यक्ति से 50 हजार रपए मांगने के आरोप में एक आयकर अधिकारी और दो अन्यों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि एजेंसी ने कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए हाल ही में आयकर विभाग, फतेहबाद के आयकर अधिकारी सी बी नारंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुशील सिंगला और बिचौलिये महेंद्र कुमार को हिरासत में लिया। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऐसा आरोप है कि आयकर विभाग, फतेहबाद के आयकर अधिकारी ने शिकायतकर्ता से वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान उसके एचडीएफसी बैंक खाते में जमा कराए धन के लिए आयकर रिटर्न ना भरने के मामले में 75,000 रुपये की रिश्वत मांगी। इस शिकायत पर आयकर अधिकारी और एक सीए (निजी व्यक्ति) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया कि ऐसा आरोप है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए पैसे दिए जाने थे। प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। उन्होंने कहा, ''''आरोपी के आवासीय और कार्यालय परिसर पर तलाशी ली गई। आयकर अधिकारी से जुड़ी करीब दो करोड़ रुपये की संपत्तियों के दस्तावेज और अन्य फाइलें बरामद की गई।'

सत्तापक्ष के निशाने पर रहा पीडब्ल्यूडी विभाग

नई दिल्ली। विधानसभा में पीडब्ल्यूडी विभाग सत्तापक्ष के निशाने पर रहा। नियम-280 के तहत चर्चा में सत्तापक्ष के अधिकांश विधायकों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वह उनकी नहीं सुनते हैं। पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर भी विधायकों ने हमला बोला। इसके साथ ही नियम 55 के तहत चर्चा में सत्तापक्ष के विधायकों ने केंद्र से मांग की कि सीलिंग पर मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आए जिससे गरीबों की रोजी रोटी को बचाया जा सके। नियम-280 के तहत सदन में अपनी बात रखते हुए विधायक जगदीप सिंह ने पीडब्ल्यूडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर जबरदस्त अतिक्रमण हो गया है। ठेली-पटरी वालों ने जगह-जगह सड़क पर ही कब्जा जमा लिया है। सड़कें टूटी हुई हैं जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोंडली के विधायक मनोज कुमार ने कहा कि इस समय बरसात का मौसम नहीं लेकिन उनके इलाके में अभी भी सड़कों पर गंदा पानी भरा हुआ है। उनका दावा था कि वह विधानसभा आते समय रास्ते से फोटो लेकर भी आए हैं। विजेंद्र गर्ग ने दिल्ली में अपराध बढ़ने का मामला उठाया। विधायक एसके बग्गा ने भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जमकर कोसा। भावना गौड़ ने अनधिकृत कालोनियों में अनधिकृत निर्माण का मामला उठाया। उनका आरोप था कि बिल्डर माफिया पुलिस व संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके अनधिकृत निर्माण कर रहे हैं। इस निर्माण में बड़े स्तर पर पेयजल की बर्बादी की जा रही है। सीलिंग पर केंद्र लाए अध्यादेश : सत्तापक्षनियम-55 के तहत चर्चा में सीलिंग के मुद्दे पर सत्तापक्ष ने केंद्र पर निशाना साधा।

जम्मू में बृहस्पतिवार को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती से पहले शोभा यात्रा निकालते सिख श्रद्धालु।

संगम की रेती में सजी कुम्भनगरी, पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को

प्रयागराज। गंगा-यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर दिव्य कुम्भ की धर्म नगरी बस चुकी है। यहां दूर-दूर के आस्थावान लोगों का मेले में आना शुरू हो गया है। अखाड़ों की पेशवाई प्रारंभ हो गयी है। मकर संक्रांति के दिन प्रथम शाही स्नान से पूर्व सभी अखाड़े भव्य पेशवाई के साथ अपनी छावनी में पहुंच जाएंगे।

3200 बीघे में फैले मेले में चारों और आस्था और अटूट श्रद्धा का सैलाब है। तपस्या का प्रतिमान माना जाने वाला मेला इस बार अध्यात्म के साथ आधुनिकता के रंगम में रंगा है। वैश्विक स्तर पर कुम्भ की छटा बिखरने लगी है। फाफामऊ से लेकर अरैल और दारागंज से झूंसी तक फैली कुम्भनगरी 20 सेक्टर में बंटी है।

कुम्भ का अर्थ

कुम्भ एक विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला नहीं बल्कि इसके कई मायने हैं। चिंतकों, विचारकों का मानना है कि कुम्भ प्रकृति और मानव जीवन का संयोजन है। कुम्भ आत्म प्रकाश का मार्ग है। कुम्भ जीवन की गतिशीलता है। कुम्भ ऊर्जा का स्रोत है। कुम्भ मानवता का प्रतीक है। कुम्भ आध्यात्मिक चेतना का प्रवाह है। कुम्भ समस्त संस्कृतियों का संगम है।

प्रयाग में कुम्भ

ज्योतिष गणना के अनुसार वृहस्पति के मेष राशि में प्रवेश होने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में आने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में संगम तट पर कुम्भ का आयोजन होता है।

मुख्य स्नान पर्व की तिथि
मकर संक्रांति : 15 जनवरी
पौष पूर्णिमा : 21 जनवरी
मौनी अमावस्या : 4 फरवरी
वसंत पंचमी : 10 फरवरी
माघ पूर्णिमा : 19 फरवरी
महाशिवरात्रि : 4 मार्च

सरकारी रैन बसेरों की हालत खस्ता : भाजपा

रैन बसेरों में नहीं हैं पर्याप्त सुविधाएं : मनोज तिवारी

नई दिल्ली। राजधानी के रैन बसेरों की अव्यवस्था पर बृहस्पतिवार को प्रदेश भाजपा ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला। पार्टी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि सरकारी रैन बसेरों की स्थिति इतनी खराब है कि इस हाड़ कंपाने वाली सर्दी में लोग सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं। दिल्ली सरकार भले ही दावा कर रही है कि उसके पास 200 रैन बसेरे पर्याप्त सुविधाओं से लैस हैं।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने रात्रि में मौके पर जाकर कई रैन बसेरों का सच्चाई जानने का प्रयास किया।

रैन बसेरों में लोग परेशान हैं, उन्हें कंबल मिलना तो दूर, जगह भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लोग जमीन पर सोते दिख रहे हैं। अध्यक्ष ने कई वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के दावे पूरी तरह फेल हैं। रैन बसेरों में खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ओपन बाथरूम बना दिए गए हैं।

बुधवार को रात्रि में एक बच्ची के जन्म लेने की घटका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश की राजधानी के लिए बेहद शर्मनाक है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के रैन बसेरों का बजट 80 लाख रपए है, लेकिन एक बड़ी राशि सरकार रैने बसेरों के प्रचार पर खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता इस कड़ाके की सर्दी में बेघर लोगों को कंबल आदि की व्यवस्था कर रहे हैं।

मेट्रो चलाने में समर्थ है दिल्ली सरकार

आरोप लगाया कि केंद्र साजिश कर मेट्रो फेज चार के काम को रोकना चाह रही

नई दिल्ली। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विधानसभा में मेट्रो पर जारी चर्चा में कहा कि केंद्र सरकार साजिश कर मेट्रो फेज चार के काम को रोकना चाहती है। वह मेट्रो में होने वाले संपूर्ण घाटे को दिल्ली सरकार पर डालने की बात कर रही है, जो कि सरासर गलत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग दोहराते हुए गहलोत ने कहा कि यदि केंद्र सरकार मेट्रो चलाने में असमर्थ है तो मेट्रो परिचालन का पूरा काम दिल्ली सरकार को सौंप दे।

दिल्ली सरकार मेट्रो चलाने में समर्थ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री पहले भी यह बात कह चुके हैं।

मुलायम की बहू ने किया गौ कल्याण सेस का स्वागत

लखनऊ एजेंसी। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गौ कल्याण सेस के निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अगर जनता के पैसों से गो सेवा होती है तो फिर सरकार को भी अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से निभानी चाहिए।

अपर्णा यादव ने गुरुवार को यहां कहा कि अपनी गौ माता के लिए हम यह टैक्स का बोझ सहने को तैयार हैं लेकिन सरकार को इस पैसे का सही ढ़ंग से इस्तेमाल करना चाहिए। सेस लगने के बाद कोई भी गाय सड़क पर आवारा घूमती न दिखे। उन्होंने कहा कि गाय सड़क पर आवारा घूमती हैं और कूड़ा-कचरा खाकर मरने को मजबूर हैं। कूड़ा-कचरा खाने से पन्नियां गाय के पेट में चली जाती हैं जो बाद में उसकी मृत्यु का कारण बनती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में ही किसानों ने हज़ारों गौ माताओं को ज़िलों के प्रशासनिक मुख्यालय पर ले जाकर छोड़ दिया क्योंकि गौ माता के चलते उनके खेत ख़राब हो रहे थे।

सरकार यह भी देखे कि जिन लोगों ने आवासीय इलाक़ों में डेयरी खोल रखी हैं वो अपनी गायों के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार हों। हाल में योगी मंत्रिमंडल ने गौ कल्याण सेस लगाने का निर्णय लिया है।

16 निगमों में छुट्टा गौवंश के लिए 17.52 करोड़ मंजूर

प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 16 नगर निगमों में छुट्टा गौवंश के रखरखाव के लिए स्थापित गोशालाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 17.52 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। इस धनराशि से अलीगढ़, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, मथुरा, अयोध्या, फिरोजाबाद, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, बरेली एवं इलाहाबाद के नगर निगमों की गोशालाओं में गोवंश का रखरखाव किया जाएगा।

प्रमुख सचिव पशुधन डा. सुधीर एम बोबडे द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि 16 नगर निगमों में गौवंश के रखरखाव के लिए हर नगर निगम 1000 गोवंश के लिए 365 दिवसों (एक वर्ष) के लिए 30 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश यानी 109.50 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी।

विवेक हत्याकांड : आरोपी पुलिसकर्मी संदीप को 96 दिन बाद जमानत

लखनऊ। सीजेएम आनंद प्रकाश सिंह ने एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या के मामले में निरुद्ध पुलिसकर्मी संदीप की जमानत अर्जी 96 दिनों बाद मंगलवार को मंजूर कर ली। उन्होंने उसे 20 हजार की दो जमानते व इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। 20 दिसंबर को विवेक तिवारी की हत्या के इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। जिसमें अभियुक्त पुलिसकर्मी प्रशांत कुमार चौधरी को हत्या (आईपीसी की धारा 302) जबकि संदीप कुमार को मारपीट (आईपीसी की धारा 323) का आरोपी बनाया गया था। अदालत में संज्ञान के मसले पर सुनवाई के दौरान विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया था। उन्होंने अभियुक्त पुलिसकर्मी संदीप कुमार के खिलाफ समान आशय से हत्या करने के आरोप में संज्ञान लेने की लिखित दलील दी थी। अभियोजन की ओर से दाखिल आरोप पत्र पर ही संज्ञान लेने की मांग की गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। बीते 24 दिसंबर को अदालत ने आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों में ही संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों का अभिरक्षा वारंट सही करने का आदेश दिया था। जबकि कल्पना तिवारी की अर्जी को निस्तारित कर दिया था। 28-29 सितंबर की रात्रि में हुई इस घटना के बाद इन दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। आईजी ने की थी जांच इस मामले के काफी तूल पकड़ने पर शासन ने आईजी सुजीत पाण्डेय के नेतृत्व में एसआईटी गठित की थी। एसआईटी ने 81 दिन में अपनी जांच पूरी की थी। इसमें ही आरोपी पुलिसकर्मी प्रशांत चौधरी को हत्या और दूसरे पुलिसकर्मी संदीप कुमार को मारपीट का अभियुक्त बनाया गया था।

यूपी: संभल में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में ठांय-ठांय करने वाले दरोगा को लगी गोली

संभल। असमोली थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह को पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ एक बदमाश व दरोगा घायल हो गया। दूसरा बदमाश कोहरा होने के कारण भाग गया। सूचना पर पहुंचे एसपी ने घेराबंदी कर भागे बदमाश को पकड़ने के लिए जंगल में काबिंग की लेकिन बदमाश हाथ नहीं आ सका। बता दें कि संभल में असमोली थाना पुलिस की बदमाशों ने मुठभेड़ में ठांय ठांय करने वाले दरोगा को लगी गोली। दो महीने पहले रिवाल्वर नहीं चलने पर दरोगा मुंह से ठांय ठांय चिल्लाया था।

मुंह से ठांय-ठांय कर बदमाशों से मुकाबला करने वाले दरोगा को मिलेगा ईनाम

थाना पुलिस को शुक्रवार की सुबह सूचना मिली कि गांव अलिया नेकपुर के पास दो शातिर बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर असमोली पुलिस अलिया नेकपुर के पास पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरु कर दी। पुलिस ने भी बदमाशों द्वारा की जा रही फायरिंग में जबाबी फायरिंग शुरु कर दी।

पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से अमरोहा जिले के डिडौली थानांतर्गत फैजगंज अशरफपुर निवासी सद्दाम पुत्र साबिर घायल हो गया वहीं दरोगा मनोज कुमार को भी छर्रे लगे हैं।

मुठभेड़ की सूचना पर एसपी यमुना प्रसाद भी कई थानों की पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर भागे बदमाश की तलाश में जंगल में काबिंग की लेकिन घना कोहरा होने के कारण बदमाश अकरम पुत्र भूरे भागने में सफल रहा।

अमेठी में स्मृति ईरानी बोलीं, कांग्रेस के लिए रामलला काल्पनिक

अमेठी। अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जोरदार स्वागत किया गया। गौरीगंज में एक निजी ढाबे पर भाजपा नेताओं ने स्मृति ईरानी का स्वागत किया। यहां से संयुक्त जिला अस्पताल पहुंची स्मृति ने फीता काटकर सीटी स्कैन सेंटर का शुभारंभ किया।

इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का राम लला से कोई वास्ता नहीं है। उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के न होने का एफिडेविट दिया है। राहुल गांधी के लिए धर्म तब चुनावी एजेंडा है,जब उनके सिर पर चुनाव आता है।

वे धर्म के तवे पर रोटियां सेंकते हैं। अगर वे करप्शन की बात करते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि मिशेल किस इटैलियन लेडी और बेटे आर का नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज अमेठी में यूपीए की दस साल के सरकार के बाद पहला सीटी स्कैन सेंटर तब खुल रहा है जब भाजपा की सरकार आई। यह साफ हो गया है कि राहुल गांधी विकास को लेकर भाजपा पर तंज कसते हैं लेकिन आज यह साफ हो गया है कि राहुल गांधी ने 15 साल सांसद रहते हुए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संसद में भाजपा के पक्ष रखने के बावजूद ये सत्य उनकी समझ नहीं आ रहा।

वे झूठ के सहारे अपनी राजनीति करना चाह रहे। उनके लिए ये विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर होता तो कांग्रेस के सांसद देश की स्पीकर पर कांग्रेस के नेता कागज न फेंकते। उन्होंने कहा कि 2014 में हमने जनता से वायदा किया था कि राहुल गांधी के दर्शन बार-बार होंगे। आज वही हो रहा है। फर्क यह है कि जब भाजपा के कार्यकर्ता आते हैं तो विकास होता है जबकि राहुल गांधी आते हैं तो स्वागत करवाने आते हैं।

कांग्रेस की होर्डिंगों पर कमलनाथ के विरोध में लगे पोस्टरों पर उन्होंने कहा कि राहुल ने कमलनाथ के उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी न देने की बात कही तो राहुल गांधी ने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि राहुल को महागठबंधन में बसपा,सपा,ममता किसी से आशीर्वाद नहीं मिला। ऐसे में वे प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे जो मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसे ही हैं।

संपादकीय

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता में फिर से वापसी से भारत-बांग्लादेश के बीच संबंधों में और मिठास की उम्मीद बढ़ गई है। उचित होगा कि भारत और बांग्लादेश उन मसलों को हल करें जो दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बना है। बांग्लादेश में फिर से हसीना सरकार का आना भारत के लिए सबसे मुफीद समय है। अत: हमें इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए।

नई उड़ान को तैयार बांग्लादेश

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता में फिर से वापसी से भारत-बांग्लादेश के बीच संबंधों में और मिठास की उम्मीद बढ़ गई है। अगर कहीं बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) के हाथ सत्ता लगी होती तो यह भारत के लिए चिंताजनक और दुश्वारियां पैदा करने वाला होता। यह तथ्य है कि बेगम खालिदा जिया की नेतृत्ववाली बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) पाकिस्तान समर्थक है और यह जब भी सत्ता की धुरी बनी है भारत विरोधी तत्वों और मोर्चे का समर्थन किया है, जबकि इसके उलट शेख हसीना भारत से मधुर संबंधों की हिमायती रही हैं और समय-समय पर बांग्लादेश में सक्रिय भारत विरोधी तत्वों पर लगाम कसी है। लिहाजा हसीना की वापसी से दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की उम्मीद बढ़ गई है। ध्यान देना होगा कि शेख हसीना ने चुनाव से पहले संकेत दिया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो भारत के साथ व्यापारिक-कारोबारी रिश्ते मजबूत होंगे और दोनों देशों के कूटनीतिक-रणनीतिक संबंधों को नई धार मिलेगी।

अच्छी बात यह है कि शेख हसीना भारत के साथ उग्रवाद व आतंकवाद की साझा चिंताओं के संदर्भ में गंभीर हैं और उन्होंने अपने भूक्षेत्र का गलत इस्तेमाल न होने के फर्ज को निभाया भी है। चूंकि शेख हसीना भारत की मित्र हैं ऐसे में भारत की तरफ से बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक मदद का विस्तार होना तय है। उल्लेखनीय यह है कि शेख हसीना ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और जनता ने उनका समर्थन किया। उनकी सफल आर्थिक नीतियों का परिणाम है कि 2009 से अब तक वहां प्रति व्यक्ति आय तीन गुना से अधिक हो गई है। कपड़ा उद्योग अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है और रोजी-रोजगार के धंधे का विस्तार हुआ है। माना जा रहा है कि शेख हसीना की सत्ता में वापसी से अब उन परियोजनाओं में तेजी आएगी जो पाइपलाइन में हैं। यानी अब बांग्लादेश भारत और जापान के सहयोग से पायरा तट के समीप गहरे समुद्र में निर्मित होने वाले बंदरगाह में तेजी आएगी। अगर यह बंदरगाह तैयार होता है तो निःसंदेह तीनों देशों के व्यापारिक हित भी सधेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश भारत की मदद से तीन रेलवे नेटवर्क पर भी काम शुरू करने वाला है।

शेख हसीना की सत्ता में वापसी इस अर्थ में ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण देश है जो चारों ओर से ऐसे पड़ोसियों से घिरा है जहां कुछ के साथ संबंध बेहतर हैं तो कुछ के साथ कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों के बीच अगर भारत और बांग्लादेश विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूती देते हैं तो निःसंदेह यह दोनों देशों के हित में होगा। वैसे भी दोनों देश परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के साथ-साथ डिफेंस कोऑपरेशन फेमवर्क, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल स्टडीज, आउटर स्पेस एवं साइबर सिक्युरिटी, इंफारमेशन टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग की नींव मजबूत कर चुके हैं। इतिहास गवाह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रगाढ़ सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ता रहा है जिससे चाहकर भी खत्म नहीं किया जा सकता। इस रिश्ते को परवान चढ़ाने के लिए ही गत वर्ष दोनों देशों ने कोलकाता से खुलना के बीच बस एवं रेल सेवा और राधिकापुर-बीरोल रेललिंक को जनता को समर्पित किया। इस पहल से दोनों देशों के बीच आवाजाही तेज होने की संभावना प्रबल हुई है वहीं सांस्कृतिक-भाषायी संबंद्धता को मजबूती मिलनी तय है। शेख हसीना की सत्ता में वापसी से दोनों देशों के नागरिकों के बीच अंतःक्रियाएं बढ़ेंगी और उच्च स्तरीय विनिमय के अलावा जनता से जनता का संबंध प्रगाढ़ होगा।

चूंकि शेख हसीन कट्टरता के खिलाफऔर आधुनिकता की प्रबल पैरोकार हैं इससे भारत के साथ शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी सहयोग की संभावना बढ़ गई है। उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच व्यापार व कारोबार में भी वृद्धि होगी। जानना जरूरी है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। बांग्लादेश में भारतीय निवेश व्यापक स्तर पर होता है। ये क्षेत्र हैं-टेक्सटाइल्स, निर्माण उद्योग, रसायन, पेंट, फार्मास्यूटिकल, अस्पताल, यात्रा, बैग, आइटी व आयुर्वेदिक उत्पाद, गरी का तेल, ऑटोमोबाएल तथा सफेद सीमेंट इत्यादि। भारत की कई कंपनियां बांग्लादेश में काम कर रही हैं। गौरतलब है कि जनवरी 2005 में भारत-म्यांमार और बांग्लादेश के बीच यांगून में एक त्रिपक्षीय बैठक हुई जिसमें बांग्लादेश से होकर पाइपलाइन द्वारा तटीय गैस को भारत ले जाने पर विमर्श हुआ। अब उम्मीद है कि हसीना सरकार इसे अमलीजामा पहनाने की दिशा में पहल तेज करेगी। भारत-बांग्लादेश संबंध इस बात का जीवंत उदाहरण है कि भारत अपने पड़ोसियों को हरसंभव यहां तक कि अपनी कीमत पर भी मदद करता है और यह बांग्लादेश को अच्छी तरह मालूम भी है। यही वजह है कि विगत वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कारोबारी गतिविधियां बढ़ी हैं।

गौर करें तो दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। बांग्लादेश प्रायः यह शिकायत करता रहता है कि बांग्लादेशी सामान जब भारतीय बाजारों में पहुंचता है तो उन्हें गैर-प्रशुल्क बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि भारत द्वारा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर बांग्लादेश ने कोई रुचि नहीं दिखाई अन्यथा शिकायत का मौका नहीं मिलता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बांग्लादेश लगातार भारतीय वस्तुओं को पारगमन की सुविधा देने से इंकार करता रहा है जिससे उसे राजस्व की हानि होती रही है। बांग्लादेश की राजस्व हानि का एक महत्वपूर्ण कारण तस्करी की समस्या भी है जिसे उसे रोकना होगा। उसे समझना होगा कि वह अपनी जरूरत की चीजों-खाद्य, तेल मसाले, इत्यादि की आपूर्ति भारत के लोगों को गैर जरुरी या आराम के साधनों-जापानी कैमरा, टेपरिकार्डर इत्यादि की तस्करी से करता है। सच तो यह है कि दोनों देशों के बीच व्यापार के बजाए तस्करी खूब फल-फूल रही है जिससे दोनों देशों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत को भी बांग्लादेश से शिकायत है कि उसकी भूमि तेजी से इस्लामी कट्टरपंथियों का अड्डा बन रहा है। वहां पर अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों से संबंधित कई गुट सुरक्षित अभ्यारण्य पाते हैं। पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश को भारत विरोधी कार्यवाहियों को अंजाम देने के लिए अपना अड्डा बना रखा है।

भारत की दूसरी चिंता यह है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदुओं की तादाद लगातार घट रही है। उनके अधिकार सीमित हो रहे हैं। कट्टरपंथी ताकतें जबरन इस्लाम स्वीकारने को विवश कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में हिंदुओं के पूजास्थलों पर हमले बढ़े हैं। पर अच्छी बात यह है कि शेख हसीना ने इसे गंभीरता से लेते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगाने की सकारात्मक पहल की है। चूंकि इस चुनाव में कट्टरपंथियों को मुंह की खानी पड़ी है ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि हसीना सरकार उनके खिलाफ सख्त रहेगी। उचित होगा कि भारत और बांग्लादेश उन मसलों को हल करें जो दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बना है। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विवाद का विषय नदियों के पानी के बंटवारे का है। दोनों देशों के बीच 54 सांझी नदियां हैं पर सबसे अधिक विवाद का विषय गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर है। अच्छी बात है कि दोनों देश विवादित मसले को सुलझाने के प्रति संवेदनशील हैं। जो सबसे अच्छी बात है वह यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व शेख हसीना एकदूसरे पर भरोसा करते हैं और यह संबंधों में मिठास घोलने की प्रथम शर्त है।

अरविंद जयतिलक
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

खदान में फंसे15 मजदूरों की चिंता

मेघालय की एक खदान में फंसे 15 मजदूरों को बाहर निकालने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज है। कोर्ट ने कहा है कि मजदूर जिस भी हालत में हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। सही भी है, अगर सरकारों ने लापरवाही न बरती होती तो कोर्ट नाराज न होता।

मेघालय की जयंतिया हिल्स पर एक अवैध खदान में फंसे 15 खनन मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा- 'मजदूर इतने दिन से लापता हैं। अब तक आपने क्या कदम उठाए? हम रेस्क्यू ऑपरेशन से संतुष्ट नहीं हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सब मारे जा चुके हैं, कुछ जिंदा हैं, कुछ मारे गए हैं या फिर सभी जिंदा हैं। उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए।' उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर से लेकर अब तक 21 दिन बीत चुके हैं लेकिन कुछ मजदूरों के हेलमेट छोड़कर रेस्क्यू टीम को कुछ नहीं मिला। जिस 370 फीट गहरी खदान में मजदूर फंसे हैं उसमें 70 फीट तक पानी भरा है। एनजीटी ने इस खदान से खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद यहां से खनन जारी था। 13 दिसंबर को यहां पास में बहने वाली एक नदी का पानी खदान में घुसने लगा और इसी के चलते मजदूर खदान में ही फंस गए। खदान में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की बढ़ रही मियाद को देखते हुए किसी अनहोनी की आशंका बढ़ गई है।

बता दें कि 20 खदान मजदूर, जिनमें कुछ नाबालिग भी हैं, 370 फुट गहरी खदान में उतरे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि खदान इतनी संकरी है कि एक बार में एक ही व्यक्ति नीचे उतर सकता है। अंजाने में किसी एक मजदूर ने सुरंग की दीवार को तोड़ दिया जिसकी वजह से पास की नदी का पानी खदान में घुसने लगा। इसके बाद पांच मजदूर किसी तरह से बाहर निकल आए, लेकिन 15 मजदूर खदान में फंस गए। सरकारों से भी कोई मदद नहीं मिली और काम कराने वाली कंपनी ने भी हथियार डाल दिए। एनडीआरएफ तो पूरे तरीके से तैयार थी अगर पानी निकालने के लिए उसे साधन मुहैया कराए जाते तो मजदूरों को अब तक बाहर निकाला जा सकता था। यह घटना थाइलैंड की एक अंधेरी गुफा में फंसी नाबालिग फुटबाल खिलाड़ियों की टीम की याद दिला रही है। तब थाईलैंड की सरकार ने रेस्क्यू के लिए अंतरराष्ट्रीय टीमों की मदद ली थी। दुनिया भर से टीमें पहुंच गई थीं। अंततः बच्चों को बचा लिया गया। अफसोस! मेघालय सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया।

मेघालय सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, इससे साफ है कि सरकार गंभीर नहीं थी। उनकी नजर में मजदूरों की जान की कोई कीमत ही नहीं। न तो आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त साधन थे और न ही स्किल। राज्य में रैट होल खदानों में खनन पर 2004 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। रैट होल खनन में बेहद संकरी सुरंग खोद कर खनन किया जाता है। यह तरीका बेहद खतरनाक, अवैज्ञानिक व जोखिम भरा है। प्रतिबंध के बावजूद रैट होल खदानों में अवैध रूप से खनन जारी है। मेघालय सरकार अवैध खनन की बात से इंकार करती आई है, लेकिन इस हादसे से झूठ बाहर आ चुका है। अब सरकारों को इस तरह के काम पर नियंत्रण करना ही होगा।

असुरक्षा का दंश झेलतीं बेटियां

हाल ही में उत्तराखंड में मनचलों ने कॉलेज से लौट रही एक छात्रा पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। इतना ही नहीं पीड़िता की मां को फोन करके बताया भी कि तुम्हारी बेटी को आग लगा दी है अगर तुम उसे बचा सकती हो तो बचा लो। ऐसी ही एक अफसोसनाक घटना में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सरेआम एक दसवीं कक्षा की छात्रा को दो लोगों ने जिंदा आग के हवाले कर दिया। कुछ ही समय पहले उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एक युवती के साथ दुष्कर्म न कर पाने पर उसे जिंदा जला देने का मामला सामने आया था। धनबाद में हुई एक घटना में भी नाबालिग सनकी आशिक द्वारा किशोरी को जला कर मार दिए जाने का मामला सामने आ चुका है। यह दुस्साहस की पराकाष्ठा और बेटियों की सुरक्षा से दुर्भाग्यपूर्ण हालातों की बानगी ही है कि मर्म को आहत करने वाली ऐसी घटनाएं आए दिन सुर्खियां बन रही हैं। अब हद तो यह है कि अमानवीयता की सीमा पर करने वाले ऐसे मामलों को सरेराह अंजाम दिया जा रहा है।

देश में एक समय महिलाओं और लड़कियों के साथ रेप या छेड़छाड़ की घटनाएं सुनाई देती थीं, मगर अब अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे किसी भी लड़की को सरेराह या घर में घुसकर जिंदा जला देने तक की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की घटनाएं मन को झकझोरती जरूर हैं, मगर आत्मा को जागृत नहीं करतीं। हम आज भी घटना के समय मूकदर्शक रहते हैं और अपराधियों का मनोबल बढ़ाते रहते हैं।

इससे ज्यादा डरावनी स्थितियां क्या हो सकती हैं कि कुछ समय पहले मेरठ में कुछ लड़कों ने घर में घुसकर घर में मौजूद महिलाओं के सामने ही एक लड़की पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। बर्बरता के ऐसे मामले बताते हैं कि ऐसे असुरक्षित परिवेश में बेटियों के पढ़ने और आगे बढ़ने की स्थितियां बेहद चिंतनीय हैं। यह जघन्यता और बर्बरता अब हद दर्जे तक बढ़ चुकी है कि बेटियां न अकेली सुरक्षित हैं और न ही अपनों के साथ। आखिर लड़कियों के मान को कुचलने, उनकी जिंदगी छीन लेने की यह बर्बर मानसिकता कहां से पोषण पा रही है? आज के युवाओं में कैसी सोच जड़ें जमा रही है कि न कानून का डर है और न ही समाज की चिंता। देश में अब बर्बर आपराधिक मानसिकता के बढ़ते आंकड़ों के आगे सरकार, समाज और कानून सब बेबस लगते हैं।

विचारणीय यह भी है कि ऐसी घटनाएं बेटियों की सुरक्षा से जुड़े दुर्भाग्यपूर्ण हालतों की ही नहीं समाज में पनप रही विद्रूप मानसिकता की भी बानगी हैं। दरअसल, बेटियों के प्रति सोच का दायरा आज भी बरसों पहले की तयशुदा सोच तक ही सिमटा है। तभी तो ऐसे मनचलों को एक लड़की का न कहना भी स्वीकार्य नहीं। बिना किसी खता के ही जिंदगी छीन लेने, जिंदा जला देने के इन मामलों के पीछे की यही संकीर्ण सोच है। पुरुष मानसिकता को यह स्वीकार ही नहीं है कि कोई महिला उसकी आकांक्षा के विपरीत अपनी भी एक स्वतंत्र सोच भी रख सकती है, अपने साथ हो रहे अपमानजनक बर्ताव का विरोध भी कर सकती है। उत्तराखंड में जिस लड़की को आग के हवाले किया गया उसने करीब ढाई वर्ष पहले इस आरोपी के परेशान और छेड़छाड़ करने का विरोध किया था। मेरठ में अपनों के सामने ही जिंदा जला दी गई लड़की को भी पड़ोस में रहने वाले कुछ मनचले काफी परेशान करते थे। वहीं धनबाद में हुई घटना में भी लड़का हमेशा लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था। दुस्साहस की अति यह कि वह कहता था कि मेरी बात मानो वरना जला कर मार देंगे। इन भयावह घटनाओं से जुड़ी ये सारी बातें विकृत होती सोच की उदाहरण तो हैं ही समाज या कानून का कोई भय न होने की बानगी भी हैं। यह घटनाएं ऐसे सामाजिक-पारिवारिक परिवेश को सामने रखती हैं जिसमें महिलाओं के अस्तित्व का कोई मान ही नहीं। एकतरफा प्रेम, प्रतिशोध व खुद से कमतर आंकने की सोच ने हमारे समाज में महिलाओं को केवल देह तक सीमित कर दिया है।

गौरतलब है कि ऐसी अधिकतर घटनाओं की शुरुआत हमेशा छेड़छाड़, पीछा करने और डराने-धमकाने वाले दुर्व्यवहार से होती है। दुखद ही है हमारे यहां रिपोर्ट करने के बाद भी बेटियों के साथ होने वाले ऐसे दुर्व्यवहार को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। कानूनी कार्रवाई में लचरता ही देखने को मिलती है। अपराधियों के खिलाफ सख्ती नहीं बरती जाती। अब सोचना नितांत जरूरी है कि जहां छेड़खानी के कुत्सित व्यवहार को जिंदगी का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया जाता हो फिर वहां मनचलों की हिम्मत बढ़ना हैरानी की बात नहीं है। उल्टा विरोध करने पर कई बार ऐसे मनचले प्रतिशोध लेने पर भी उतारू हो जाते हैं। देश के दूरदराज के गांवों में कई दबंगों ने छेड़खानी का विरोध करने पर पीड़ित लड़की की जान तक ले ली है। जिंदा जला देने के ये मामले भी इसी बर्बरता के उदाहरण हैं। छेड़खानी का प्रतिकार करने पर उपजी बदला लेने की भावना के चलते कई लड़कियों पर तेजाब फेंकने के मामले भी अक्सर सामने आते रहते हैं। बावजूद इसके सार्वजनिक स्थलों, सड़कों व सार्वजनिक वाहनों में होने वाला इस तरह का अभद्रतापूर्ण व्यवहार आज भी गंभीरता से नहीं लिया जाता।

इतना ही नहीं महिलाओं के साथ होने वाला छेड़छाड़ का अपराध ऐसा अपराध जिसे प्रमाणित करना बेहद कठिन हैं।कई मामलों में तो ऐसे भयावह व्यवहार के पीछे एकतरफा प्रेम का पागलपन भी होता है जिसमें लड़की का न कहना ही उनकी जान जाने की वजह बनी है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी युवा ऐसी मानसिकता के साथ बड़े हो रहे हैं जिसमें किसी लड़की का इंकार स्वीकार ही नहीं है। अब सवाल यह है कि महिलाएं भी इस देश की नागरिक हैं और आधी आबादी हैं। संविधान ने उन्हें सुरक्षा और समान से जीने का हक दिया है। यही वजह है कि ऐसे मामले सिर्फ आंकड़ों तक नहीं समेटे जा सकते। यह मानसिक बर्बरता समाज की बुनियाद हिला देने वाली है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के नारे वाले देश में अपने गली-मोहल्ले या घर में बेटियां जिस असुरक्षा को जी रही हैं, उसके पीछे मौजूद संजीदगी के अभाव को सामने रखने वाली हैं। यह दरिंदगी भरा व्यवहार उस हकीकत से रूबरू करवाता है, जिसमें महिलाओं को लेकर समानता के दर्जे की सोच व संवेदनशील व्यवहार आज भी नदारद है। ऐसे में बेटियों की सुरक्षा के लिए कई पहलुओं पर सोचा जाना बेहद जरूरी है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इन बर्बर घटनाओं को गंभीरता से लेकर ठोस कार्रवाई की जानी आवश्यक है। वरना इस दुस्साहसी व्यवहार को और विस्तार मिलेगा।

महिलाओं और लड़कियों से दरिंदगी या छेड़छाड़ का मामला आज जिस तरह से बढ़ा है, उसके लिए न तो कानून जिम्मेदार है और न ही कोई सरकार। यह हमारी ही देन है। हमें दूसरों की तकलीफों से तब तक कोई वास्ता नहीं होता, जब तक उसकी छाया हम पर न पड़े। भागमभाग की दिखावटी जिंदगी में आज भी ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत है, जो उस समय मौजूद रहते हैं, जब कोई मनचला दरिंदगी की हदें पार कर रहा होता है। उस समय उस दरिंदे से मुकाबला करने या पीड़ित को बचाने के बजाय हम या तो कायरों की तरह चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं या आंखें फेर लेते हैं या फिर निकल जाते हैं। हमारी इसी मानसिकता की देन है कि अपराधी तत्व मनमानी करने पर उतारू हैं। अगर हम समय रहते अपराधियों का मुकाबला शुरू कर दें तो न सिर्फ उनके हौसले पस्त होंगे, बल्कि देश में लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षित परिवेश देने के लिए कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

सरकार या कानून तब तक अपना काम नहीं कर सकते जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे। कानून अपना काम तब करेगा जब अपराधी उसके सामने होगा। मगर हम अभी अपराधियों को बच निकलने का मार्ग दे रहे हैं। उत्तराखंड, यूपी और रांची में पीड़ित के साथ जब मनमानी की जा रही होगी, तब भी वहां कई लोग मौजूद रहे होंगे, पर कोई हिम्मत नहीं जुटा सका। अगर हिम्मत करते तो वे सब बच जातीं।

मोनिका शर्मा
(वरिष्ठ पत्रकार)

ट्विटर

हमारा देश खनिज संपदा से संपन्न है, लेकिन खनन संबंधी पूरे संसाधन और बचाव अभियान की पुख्ता और कारगर व्यवस्था का तंत्र खड़ा नहीं कर पाए हैं।

विजय विद्रोही, वरिष्ठ पत्रकार

खदान में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। खदान इतनी संकरी है कि बचाव काम में देरी हो रही है। हमारी सरकार पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं।

कॉन्रेड संगमा, मुख्यमंत्री मेघालय

सत्यार्थ

संकल्प से बन जाते हैं सारे काम

बाल्टिमोर में टायरोन नामक एक बालक उल्टी रखी दूध की क्रेटों पर खड़े होकर स्लैम डंक किया करता था। उसे खेलों से बहुत लगाव था। जैसे-जैसे वह बड़ा होता गया, वैसे-वैसे उसका झुकाव एनबीए बास्केट -बॉल की तरफ होता गया। वह हर तरह से स्वस्थ व चुस्त था, लेकिन उसका कद महज पांच फुट तीन इंच ही था, जबकि एनबीए बास्केटबॉल खेलने वाले सभी खिलाड़ी छह फुट से ऊपर थे। जब टायरोन लोगों से यह कहता कि वह एनबीए बास्केटबॉल खेलना चाहता है तो वे उस पर व्यंग्य करते और कहते- यह खेल छोटे कद के लोगों के लिए नहीं है। जब लोग उससे उसके छोटे कद का जिक्र कर जाने-अनजाने उसका उत्साह तोड़ने की कोशिश करते, तब वह कहता- बेशक मेरा कद लंबा नहीं है, मगर मेरी गति, स्टेमिना एवं विस्फोटकता शायद एनबीए बास्केटबॉल के अन्य खिलाड़ियों से अधिक है। तुम सब देखना, मैं अपने इन्हीं गुणों के कारण एक दिन एनबीए बास्केटबॉल का खिलाड़ी बन कर रहूंगा। लोग उसकी सकारात्मक बातें सुनकर चुप हो जाते। वह सफल होने के लिए प्रतिबद्ध था, इसलिए नकारात्मक बोलने वाले लोगों को नजर-अंदाज करते हुए अपनी खेलने की क्षमता बढ़ाता रहा। अंततः वह दिन भी आया, जब उसका चुनाव एनबीए बास्केटबॉल के लिए कर लिया गया। उस की विशेष खेल क्षमता को देखकर सभी दंग रह गए। टायरोन ने अपनी इच्छा को अपने संकल्प के माध्यम से पूरा कर लिया था। गौर करने की बात यह है कि पांच फुट तीन इंच के टायरोन एनबीए के इतिहास में सबसे छोटे खिलाड़ी थे और आज तक हैं। टायरोन की संकल्प शक्ति के आगे कद की बाधा आड़े नहीं आ पाई और उन्होंने सहजता से इस पर विजय पाकर इतिहास रच दिया।

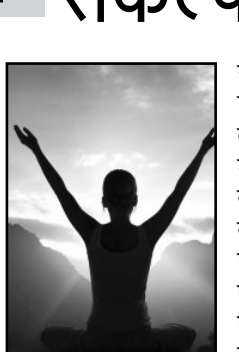

रेनू सैनी

सार समाचार

अमेरिका में हुआ भयानक सड़क हादसा, एक्सीडेंट में सात लोगों की मौत

फोर्ट लाउडरडेल (अमेरिका)। अमेरिका में फ्लोरिडा हाइवे पर बृहस्पतिवार को सामान से लदे ट्रकों और दो यात्री वाहनों के बीच टक्कर के बाद सड़क पर फैले डीजल में आग लगने से सात लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। 'गैनेसविले सन' की खबर के मुताबिक हादसे में सात लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। आपातकालीन विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विभाग का कहना है कि वह इस मामले की हत्या के नजरिये से जांच कर रहे हैं। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं की जा सकी है। हादसे के बाद हाइवे को घटनास्थल के नजदीक दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है।

पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर और सख्ती, जेल में कोठरी खुद साफ करेंगे

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जेल में अपनी कोठरी की साफ-सफाई खुद ही करनी होगी क्योंकि पंजाब की प्रांतीय सरकार ने उन्हें कैदी मुहैया कराने से बुधवार को इनकार कर दिया जो उनके सेवादार के तौर पर काम करता है। अल अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल की सजा काट रहे हैं और एक पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर वह सेवादार समेत अन्य बेहतर सुविधाओं के हकदार हैं। डॉन समाचारपत्र के मुताबिक, पंजाब के जेल महानिरीक्षक शाहिद सलीम बेग ने बुधवार को कहा कि पंजाब सरकार ने शरीफ को बंदी मुहैया नहीं कराने का फैसला किया है जो उनके सेवादार के तौर पर काम करता। बेग ने कहा कि शरीफ को अपनी कोठरी खुद ही व्यवस्थित रखनी होगी। जेल प्रमुख ने कहा कि अल अजीजिया स्टील मिल्स/हिल मेट इस्टैब्लिशमेंट मामले में मिली सात साल की 'सश्रम' कैद पूरी करने के लिए नवाज शरीफ को अपनी कोठरी स्वयं व्यवस्थित रखने को कहा गया है। पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर की उपस्थिति में गवर्नर हाउस में, जेल महानिरीक्षक बेग ने कहा कि शरीफ का मामला अत्यंत संवेदनशील है और उन्हें जेल में उनकी बैरक से भी बाहर जाने नहीं दिया जा सकता।

अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप होने के कारण लोगों को नहीं मिल रहा शादी का लाइसेंस

वॉशिंगटन। अमेरिकी नागरिक डैन पोलक और उनकी होने वाली पत्नी अपनी शादी का प्रमाण पत्र लेने वॉशिंगटन में 'मैरिज ब्यूरो' पहुंचे, लेकिन सरकारी कामकाज ठप होने के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा. डैन पोलक और उनकी पत्नी की तरह अमेरिका में कई ऐसे जोड़े हैं जो सरकारी कामकाज ठप होने के कारण अपने विवाह को कानूनी दर्जा नहीं दे पा रहे हैं.

पोलक ने कहा, ''जब हम ब्यूरो पहुंचे और तो उन्होंने विनम्रता के साथ हमें लौटा दिया और कहा कि सरकारी कामकाज फिर से आरंभ होने तक लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे.'' पूर्व निर्धारित विवाह समारोह में दो ही दिन शेष होने के कारण उन्होंने विवाह कार्यक्रम में बदलाव नहीं करने का फैसला किया, लेकिन अपनी शादी को कानूनी दर्जा देने के लिए वे कामकाज शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं.

इस दंपति ने ट्विटर पर अपनी कहानी पोस्ट की है जो सरकारी कामकाज ठप होने के कारण आम लोगों को हो रही परेशानियों का एक उदाहरण है. सरकारी कामकाज जल्द पुन- शुरू होने का आसार नहीं दिखने के कारण नवविवाहित जोड़ों की चिंता बढ़ने लगी है. पोलक की ही तरह क्लेयर ओ रौरके की 12 जनवरी को शादी तय है. उन्होंने कहा, ''हम विवाह करेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि कागजी काम भी जल्द पूरा हो.''

सिंगापुर कर रहा बिल्कुल नई शुरुआत ये है जमीन के नीचे का मास्टर प्लान

नई दिल्ली (एजेंसी)।

पूरी दुनिया में लोगों के रहने के लिए लगातार जगह कम होती जा रही है। ऐसे में सिंगापुर बिल्कुल नया मॉडल लेकर सामने आया है। उसके इस मॉडल का नाम अंडरग्राउंड मास्टर प्लान है। सुनकर भले ही आपको ये कुछ अटपटा लगे, लेकिन यह सच है। दरसअल, सिंगापुर में जनसंख्या के बढ़ने के साथ कम होती जगह को नए सिरे से मास्टर प्लान के तहत बसाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि यह मास्टर प्लान जमीन के नीचे के लिए है। अब भी यदि आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ये भी बता देते हैं कि सिंगापुर में जमीन के ऊपरी हिस्से को इंसानों के रहने के लिए और उसके निचले हिस्से को अन्य चीजों के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा है।

इसी वर्ष से लागू होगा अंडरग्राउंड मास्टर प्लान : सिंगापुर का यह बिल्कुल नया तरह का मास्टर प्लान इसी वर्ष से लागू होने वाला है। इसकी खासियत ये है कि जमीन के अंदर के हिस्से का इस्तेमाल अब पूरी तरह से बदल जाएगा। इस हिस्से में ट्रांसपोट सिस्टम से लेकर अन्य जरूरी जीजें बनाई जाएंगी। इससे सिंगापुर अपनी एक नई पहचान भी बनाने जा रहा है। अंडरग्रांड मास्टर प्लान के तहत इंसानों के इस्तेमाल वाली सुविधाएं जैसे रेल लाइन, पैदल चलने के लिए रास्ते, पांच-लेन वाले राजमार्ग और एयर-कंडीशनिंग की पाइपों को जमीन के नीचे किया जाएगा। प्लान के तहत इनमें से काफी कुछ काम को कर भी लिया गया है।

सिंगापुर की पहचान

आपको बता दें कि सिंगापुर अपने सुपरट्री वर्टिकल गार्डन की मीनारों से लेकर रात में फॉर्मूला वन रेसिंग के लिए पहचाना जाता है। इसके अलावा भी यहां कई दूसरी चीजें आकर्षण का केंद्र हैं। लेकिन अब सिंगापुर बिल्कुल नया कंसेप्ट लेकर सामने आ रहा है। यदि इसमें वह सफल हो गया तो वह पूरी दुनिया को एक क्रांतिकारी राह दिखा देगा।

रीक्लेम पॉलिसी हुई बंद

सिंगापुर में करीब 56 लाख लोग रहते हैं जिनकी संख्या 2030 तक 69 लाख हो जाएगी। ऐसे में लोगों के लिए जमीन का कम पड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सिंगापुर के इस अंडरग्राउंड मास्टर प्लान के पीछे दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि सिंगापुर में कई दशकों से नई जमीन को चली आ रही रीक्लेम पॉलिसी को अब बंद कर दिया। इसके तहत खाली और बेकार पड़ी जमीन को रिहाइश के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा था। सिंगापुर के साथ एक बड़ी समस्या ये भी है कि क्लामेट चेंज के तहत हो रहे बदलावों के बाद समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अंडरग्राउंड मास्टर प्लान में डाटा सेंटर, यूटिलिटी प्लांट, बस डिपो सहित गहरी-सुरंग वाली सीवेज प्रणाली, भंडारण और पानी के जलाशय भी होंगे। यहां पर आपको ये भी बता दें कि सिंगापुर का एक्सप्रेस-वे नेटवर्क लगभग 180 किलोमीटर का है। इसमें से करीब दस फीसद जमीन के अंदर ही है। आने वाले समय में इसका विस्तार किया जाएगा।

जानकार भी मानते हैं सही

जानकार भी मान रहे हैं कि बदलते मौसम का असर कई चीजों पर पड़ रहा है। ऐसे में कई बार हालात बेहद कम समय में सोच से कहीं अधिक खराब हो जाते हैं। इसलिए उनको जमीन के नीचे ले जाना अच्छा उपाय है। इस मास्टर प्लान के लिए 3ष्ठ तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इस 3ष्ठ तकनीक की मदद से बहुत से डाटा का विश्लेषण हो सकेगा, जिससे ना सिर्फ शहरी नियोजन में मदद मिलेगी बल्कि कोई आपदा भी संभाली जा सकती है। हालांकि सिंगापुर में जिस कंसेप्ट पर काम किया जा रहा है वह पूरी तरह से नया नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बड़े और व्यापक पैमाने पर इसकी शुरुआत करना जरूर नया है। यहां पर ये भी बताना लाजमी हो जाता है कि हाल ही में टेस्ला कंपनी के प्रमुख एलन मस्क की कंपनी ने अमेरिका में एक करोड़ डॉलर की लागत से तकरीबन दो किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड टनल बनाई है। यह सुरंग ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए बनाई गई है। इस सुरंग में 150 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकती है।

अमेरिका ने चीन की यात्रा करने पर 'अति सतर्कता बरतने' की चेतावनी दी

वाशिंगटन। अमेरिका ने चीन की यात्रा कर रहे अपने नागरिकों को अति सतर्कता बरतने की सलाह दी है क्योंकि चीन में 'स्थानीय कानूनों को मनमाने तरीके से लागू किया जा रहा है'' और अमेरिका-चीन की दोहरी नागरिकता वाले लोगों पर विशेष प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अमेरिका ने चीनी अधिकारियों द्वारा दो कनाडाई नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद यह चेतावनी जारी की है। नयी यात्रा चेतावनी में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी नागरिकों को चीन से बाहर निकलने से रोकने के लिए 'एग्जिट प्रतिबंध' लगाने शुरू कर दिए हैं। कुछ मामलों में वह वर्षों तक अमेरिकी नागरिकों को चीन में रोके रखते हैं। चेतावनी में आरोप लगाया गया है कि चीन 'एग्जिट प्रतिबंध' का इस्तेमाल दंडात्मक तरीके से करता है ताकि वह अमेरिकी नागरिकों को चीन सरकार की जांच में भाग लेने के लिए मजबूर कर सके, लोगों को चीन वापस लौटने का लालच दे सके और दीवानी विवादों का फैसला चीनी पक्षकारों के पक्ष कराने में सहयोग/सहायता ले सके। विदेश मंत्रालय ने कहा, 'ज्यादातर मामलों में अमेरिकी नागरिकों को एग्जिट प्रतिबंध के बारे में तब पता चलता है जब वह चीन छोड़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें यह भी नहीं पता चल पाता कि यह प्रतिबंध कब तक चलेगा। एक्जिट प्रतिबंध के दौरान अमेरिकी नागरिकों को प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें धमकाया भी जाता है।' चेतावनी में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों को दूतावास से संपर्क किए बगैर और उनका अपराध बताए बगैर गिरफ्तार कर लिया जाता है। विदेश मंत्रालय ने आगाह किया, 'अमेरिकी नागरिकों से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कारणों का हवाला देते हुए लंबे समय तक पूछताछ की जाती है और उनकी हिरासत अवधि भी बढ़ा दी जाती है।'

अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अध्यक्ष चुनी गई डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका में विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी अंतत- तीन जनवरी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अध्यक्ष चुन ली गईं। पेलोसी के समक्ष इस पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैककार्थी खड़े थे। सदन में पेलोसी को 220 वोट मिले जबकि मैककार्थी को 192 मत मिले। गौरतलब है कि अमेरिका में नवंबर 2018 में हुए मध्यावधि चुनावों से पहले लोगों को संदेह था कि क्या 78 वर्षीय पेलोसी सदन में अपनी पार्टी को बहुमत दिला सकेंगी और वह अध्यक्ष बन सकेंगी। लेकिन चुनाव में मिली जीत और तीन जनवरी को उनके चयन ने सभी सवालों का जवाब दे दिया।

पेलोसी ने हालांकि अपने चुनाव प्रचार के दौरान यह स्पष्ट किया था कि वह सिर्फ चार साल के लिए नेतृत्व संभालेंगी। उसके बाद नेतृत्व अगली पीढ़ी के हाथों में चला जाएगा। पेलोसी सदन के स्पीकर/अध्यक्ष के पद पर चुनी जाने वाली एकमात्र महिला हैं। सदन में

पार्टी की कमान संभालने वाली पेलोसी पर अपनी पार्टी के सदस्यों की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने का दबाव है। लेकिन वह इसे विभाजनकारी गतिविधि बताती हैं।

उनका कहना है, ''हमें किसी के खिलाफ महाभियोग राजनीतिक कारणों से नहीं चलाना चाहिए और न ही राजनीतिक कारणों से किसी के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने को रोकना चाहिए।'' पेलोसी का कहना है कि वह 2016 के चुनावों में रूसी हस्तक्षेप के संबंध में विशेष अधिवक्ता रॉबर्ट मूलर की रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं। उनका कहना है कि सिर्फ सदन ही महाभियोग पर निर्णय ले सकता है।

ट्रंप ने कैलिफोर्निया में मारे गए भारतीय मूल के पुलिस अधिकारी के परिवार से बात की

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कैलिफोर्निया में मारे गए भारतीय मूल के पुलिस अधिकारी रोनिल 'रोन' सिंह के परिजनों और साथी पुलिस अधिकारियों से गुरुवार को बातचीत की। सिंह की हत्या कथित रूप से अवैध अप्रवास व्यक्ति ने गोली मार कर की थी। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी है। न्यूमेन पुलिस विभाग में अधिकारी रोनिल सिंह (33) 26 दिसंबर को अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, उसी दिन स्थानीय समयानुसार देर रात एक बजे उनको गोली मारी गई जिसके बाद उनकी मौत हो गई।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैन्डर्स ने कहा, ÷आज दोपहर, राष्ट्रपति ट्रंप ने पुलिस अधिकारी रोनिल 'रोन' सिंह के परिवार और न्यूमेन विभाग में उनके साथी पुलिसकर्मियों से बात की। सिंह जुलाई

2011 में पुलिस विभाग में शामिल हुए थे।

सैन्डर्स ने कहा, 'राष्ट्रपति ने देश के नागरिकों के लिये अधिकारी की सेवाओं की प्रशंसा की है। उन्होंने संवेदनाएं जताते हुए मामले की तेजी से जांच करने और संदिग्ध को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया।' उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति ने सिंह की पत्नी अनामिका 'मिका' चांद सिंह, न्यूमेन कैलिफोर्निया पुलिस प्रमुख रैंडी रिचर्डसन और स्टेनिस्लॉस काउंटी, कैलिफोर्निया के शैरिफ एडम क्रिश्चिनसन से फोन पर बात की।'

कैलिफोर्निया पुलिस ने इस मामले में मेक्सिको से आए एक अवैध आप्रवासी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान 33 वर्षीय गुस्ताव पेरेज एरिएगा के रूप में हुई है।

ब्राजील में अमेरिकी सेना बनाएगी अड्डा! जल्द वार्ता कर सकते हैं राष्ट्रपति

ब्रासीलिया (एजेंसी)।

ब्राजील के घोर दक्षिणपंथी नये राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो ने गुरुवार को कहा कि वह भविष्य में देश में अमेरिकी सैन्य अड्डे की स्थापना को लेकर अमेरिका के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं. इस घोषणा के साथ ही उन्होंने अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते बनाने की भी अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया है. इस हफ्ते अपना पदभार संभालने वाले 63 वर्षीय पूर्व पैराट्रूपर ने एसबीटी टेलीविजन से कहा, ÷यह देखते हुए कि विश्व में क्या कुछ हो सकता है, कौन जानता है कि भविष्य में हमें इस विषय पर चर्चा करनी पड़े.' उन्होंने कहा, 'इसका वास्तविक मुद्दा मात्र सांकेतिक हो सकता है. वर्तमान में अमेरिकी, चीनी, रूसी सशस्त्र बल बिना सैन्य अड्डों के पूरे विश्व में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सक्षम हैं.' बोलसोनारो ने ब्राजील को एक नई दिशा देने का प्रण लिया है, जो वर्षों तक रही उसकी वामपंथी एवं मध्यमार्गी राजनीति से पूरी तरह से दूर होगी. उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ से बुधवार को कहा था कि दोनों देश अब 'दोस्त हैं.' साथ ही उन्होंने ब्राजील में चीनी निवेश के प्रति विरोध जताते हुए खुद को अमेरिका के पक्ष में बताया

था.

सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर पाक ने खोला मुँह, कहा- यह सिर्फ भारतीयों की कल्पना है

इस्लामाबाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान ने एक बार फिर बृहस्पतिवार को 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को 'भारतीय कल्पना की उड़ान' करार देकर खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। भारतीय सेना ने 26 सितंबर, 2016 को नियंत्रण रेखा के पार आतंकी लांच पैडों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे हमलों से इनकार किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल से उनके साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नये साल के मौके पर एक साक्षात्कार में सर्जिकल स्ट्राइक का किये गये उल्लेख के बारे में पूछा गया तब उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा, 'ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। यह भारतीय कल्पना की उड़ान भर है। खुद भारतीय मीडिया भी अपनी सरकार के दावे पर संदेह कर रहा है।' मंगलवार को एक साक्षात्कार में मोदी ने कहा था कि यह सोचना बड़ी भूल होगी कि बस 'एक लड़ाई' से पाकिस्तान अपना तौर तरीके बदलेगा। उनका इशारा 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक की ओर था। जब फैजल से भारत बौर पाकिस्तान के बीच वार्ता के बारे पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'यदि भारत वार्ता से संकोच करता है तो हम कुछ खास नहीं कर सकते। दोनों को ही आगे आना होगा। इस मामले पर हमारा रुख स्पष्ट है।' भारत ने भी पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। भारत पाकिस्तान संबंध को 'मुश्किल और जटिल' करार देते हुए उन्होंने कहा, 'हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।'

जापान में एक अप्रैल को होगी राजशाही के नए दौर की घोषणा

टोक्यो (एजेंसी)।

जापान के प्रधानमंत्री ने नववर्ष पर संवाददाता सम्मेलन में पुष्टि की कि नये सम्राट के शासन की घोषणा एक अप्रैल को होगी. जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने शुक्रवार को कहा कि 2019 जापान के लिए बहुत अहम समय होगा. उन्होंने एक बार फिर सम्राट अकीहितो के राजगद्दी छोड़ने की बात का जिक्र किया. अपने गिरते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अकीहितो ने परंपरा से हटकर अपने जीवनकाल में ही स्वेच्छा से राजगद्दी छोड़ने का निर्णय किया है. उनके पुत्र एक मई को नये सम्राट के रूप में कार्यभार संभालेंगे. राजशाही के नए दौर का नाम महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह पारंपरिक जापानी कैलेंडर में साल की प्रकृति तय करने के लिये जरूरी होता है. नये सम्राट के पद भार संभालने को लेकर पारंपरिक रस्मों ने लोगों का ध्यान खींचा कि किस तरह से आधुनिकता के बावजूद जापान ने अपनी परंपराओं को संजोये रखा है. इस सप्ताह के शुरू में महल की बालकनी से अकीहितो ने हाथ हिलाकर प्रजा का अभिवादन किया. तब वहां डेढ़ लाख से अधिक लोग मौजूद थे जो अकीहितो के लिये एक रिकॉर्ड था.

70 साल में पहली बार जनसंख्या घटने से चीन परेशान, जानें- कैसा है भारत का हाल

नई दिल्ली (एजेंसी)।

दुनिया का सबसे आबादी वाला देश चीन। कल तक चीन के लिए उसकी सबसे ज्यादा आबादी ही समस्या बनी हुई थी। लिहाजा चीन ने आबादी नियंत्रित करने के लिए कानून लागू किया। अब चीन के लिए उसकी घटती आबादी चिंता का विषय बन चुकी है। चीन में 2018 की जनसंख्या पर आयी रिपोर्ट चौंकाने वाली है। साथ ही चीन के लिए भविष्य की बड़ी समस्या की तरफ भी इशारा करती है। ऐसे में हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में दुनिया का दूसरा देश होने के कारण भारत की क्या स्थिति है।

चीन में जनसांख्यिकीय संकट: विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में पहली बार कम हुई जनसंख्या भविष्य की बड़ी चुनौती की तरफ इशारा कर रही है। इससे चीन की धीमी पड़ चुकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। लिहाजा इसे चीन के ऊपर एक जनसांख्यिकीय संकट के तौर पर देखा जाना चाहिए। चाइनीज विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को इस से निपटने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी।

चीन की जनसंख्या नियंत्रण नीति: चीन की आबादी कुछ तकरीबन एक करोड़ 40 लाख है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। कुछ दशक पहले तक चीन की लगातार बढ़ रही आबादी उसके लिए चिंता का सबब बनी हुई थी। इसे नियंत्रित करने के लिए चीन ने वर्ष 1979 में एक बच्चे की नीति बना दी थी। इसके तहत कपल को केवल एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति थी। कुछ साल पहले चीन को एहसास हुआ कि देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके अनुपात में युवाओं की जनसंख्या काफी कम हो रही है। लिहाजा वर्ष 2016 में चीन ने एक बच्चे की नीति को निरस्त कर दो बच्चों की नीति बना दी। मतलब चीन में अब एक कपल दो बच्चे पैदा कर सकता है।

दो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते चीनी नागरिक

अमेरिका के रहने वाले रिसर्चर और विद्वान यी फुक्शियन का कहना है कि दो बच्चों की नीति बनाने के बाद भी वर्ष 2018 में चीन में जन्मदर 25 लाख प्रति साल कम हो गई है, जबकि नई नीती में हर साल करीब 7,90,000 बच्चे ज्यादा पैदा होने की उम्मीद थी। इसकी वजह ये है कि चीन में लोग अब दो बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते। इसकी वजह वहां की महंगी शिक्षा, मेडिकल सुविधाएं और घर के अन्य खर्च हैं। ऐसे में लोग अच्छी परवरिश करने के लिए एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञ इस बात की भी आशंका जता रहे हैं कि चीन में घटती आबादी के इस ट्रेंड को अब शायद बदला ना जा सके, क्योंकि चीन में बच्चा पैदा करने की सही उम्र की महिलाओं की संख्या में भी काफी कमी आयी है।

बीते वर्ष 12.70 लाख घटी चीनी आबादी: रिसर्चर यी फुक्शियन के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में चीन में लगभग एक करोड़ 15 लाख लोगों की मौत हुई थी। इससे पिछले वर्ष उनकी आबादी 12.70 लाख घट गई है। विशेषज्ञों के अनुसार 70 साल पहले वर्ष 1949 में चीन बनने के बाद ये पहली बार हुआ है, जब देश की आबादी घटी है।

विशेषज्ञों का सुझाव: विशेषज्ञों ने चीन सरकार को भविष्य के इस खतरे के प्रति आगाह करते हुए चेतावनी दी है कि सरकार दो बच्चों की नीति को खत्म करे। इसकी जगह सरकार को अच्छी मैटरनिटी लीव और बच्चों के माता-पिता को टैक्स ब्रेक जैसी राहत देनी चाहिए। अगर सरकार ने जल्द आवश्यक कदम नहीं उठाए तो चीन में बुजुर्ग आबादी की समस्या जापान से भी गंभीर हो जाएगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। बुजुर्गों की आबादी बढ़ने से पेंशन और हेल्थकेयर सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा।

मजबूत है भारत की स्थिति: चीन को आगाह करने वाले रिसर्चर यी फुक्शियन का मानना है कि आबादी के मामले में भारत की स्थिति चीन से मजबूत है। इसकी वजह भारत में सबसे ज्यादा युवा आबादी का होना है। फुक्शियन का मानना है कि इसी युवा जनसंख्या की बदौलत चीन की जगह भारत भविष्य में अमेरिकन अर्थव्यवस्था को टेकओवर करेगा। भारत के लिए ये अच्छा संकेत है।

दो माह पहले ही मिले थे संकेत: चीन में घटती आबादी बड़ी समस्या बनने वाली है, इसके संकेत करीब दो माह पहले ही मिलने लगे थे। चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ ने नवंबर 2018 में राजधानी बीजिंग में जनसंख्या दर की रिपोर्ट पेश की थी।

बिना टैक्स बढ़ाए मनपा का वर्ष 2019 का ड्राफ्ट बजट पेश

नए ड्राफ्ट बजट में पुराने प्रोजेक्ट को पूर्ण करने पर दिया गया बल

सूरत । शुक्रवार को सूरत महानगर पालिका आयुक्त एम थेनाराशन द्वारा जारी किए गए वित्तीय वर्ष 2019-20 का ड्राफ्ट बजट पेश किया गया जिसमें टैक्स में बिना किसी वृद्धि के 5599 करोड़ का बजट बनाया गया बजट के संदर्भ में जानकारी देने के उद्देश्य से आयोज में मनपा कमिश्नर एम ने बताया कि इस बजट में किसी भी नए प्रोजेक्ट को शामिल नहीं किया गया है आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तथा पिछले बार कांग्रेश द्वारा टैक्स में किए गए बढ़ोतरी का जोरदार विरोध किए जाने पर बढ़ाए गए टैक्स को वापस लेना पड़ा था इस को ध्यान में रखते हुए इस बार सूरत महानगर पालिका कमिश्नर ने इस बजट में किसी प्रकार के टैक्स को बढ़ाएं बिना ही 5599 करुण का ड्राफ्ट बजट पेश किया।

पिछले डेढ़ दशक का सबसे कमजोर बजट सूरत शुक्रवार को महानगर पालिका द्वारा पेश किए गए 2,000 1920 प्राप्त बजट को पिछले दशक का सबसे कमजोर बजट कहा जा सकता है संपूर्ण विश्व में जिस शहर का नाम हीरे की तरह चमक रहा हो उस शहर में इतने कम बजट में विकास का कार्य कैसे होगा यह समझ के बाहर है 5599 करोड़ के सूचित बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया जाए तो 2515 करोड़ की रकम विकास कामों के लिए यानी की कैपिटल प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे गडर पर होगा सबसे ज्यादा खर्च मनपा के इस बजट में सबसे ज्यादा खर्च गटर लाइन तथा ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने में किया जाएगा कुल खर्च का 15ज्गड्ढा मुक्त करने में खर्च किया जाएगा आगामी 5 वर्षों में पानी के सभी कनेक्शनों के साथ लगेगा मीटर महानगर पालिका इस बजट के द्वारा आगामी 5 वर्षों में पानी के सभी कनेक्शनों के साथ मीटर लगाने जा रही है नहीं लगने वाले कनेक्शनों पर मीटर पहले से ही अनिवार्य होगा महानगर पालिका पानी के बिगाड़ को रोकने के लिए यह कदम उठा रही है। सूरत महानगर पालिका के आगामी वित्तीय वर्ष की जानकारी देते हुए मनपा कमिश्नर ने कहा कि इस बजट में शहर को कंटेनर फ्री करने तथा स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है चालू वित्त वर्ष के दौरान घरेलू कचरे के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया गया है इसमें जगह-जगह गीले तथा सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन का व्यवस्था किया गया है उन्होंने सूरत को सिटी आफ इंडिया का पुरस्कार मिलने पर सूरत के नागरिकों का अभिनंदन किया आगामी बीबर 2019 20 के लिए बजट का कर 5599 करोड़ रखा गया है जिसमें 2515 करोड़ का वजन कैपिटल खर्च पर किया जाएगा आउटकम बजट के लिए 1600 करोड़ के 393 का मौका दिया जाएगा। शहर को वैश्विक स्तर की स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प को मूल स्थान प्रदान करने की प्रतिबद्धता शहर के तमाम विस्तारो तथा घटकों तक नागरिक सुविधाएं प्रदान करने पर ब्यूटी वेकेशन स्किल अपडेशन तथा

गत वर्ष की तुलना में इस वष 48 करोड़ से अधिक आमदनी की उम्मीद

सामाजिक सुरक्षा पर्यावरण रक्षा के विशेष प्रधान ट्रैफिक तथा पर्यावरण को ध्यान में रखकर पार्किंग तथा ग्रीनबर्ग वाहनों के उपयोग पर बल सस्टेनेबल इको सिटी बनाने की तरफ विशेष ध्यान रीसाइक्लिंग ऑफ़ वाटर रिवेन्यू एनर्जी ग्रीन बेल्ट ग्रीन स्केल ब्लूज के तथा एस्केप का विकास।

बजट 2019-20 हाईलाइटस

कुल अनुमानित बजट 5599 करोड़
कुल कैपिटल बजट 2515 करोड
आउटकम बेस्ड बजट 1666 करोड,
कुल 393 कामों का समावेश

5 वर्ष में हर घर में पानी के कनेक्शन के साथ लगेगा मीटर

सूरत । बजट पेश करते समय मनपा आयुक्त ने एक महत्वपूर्ण बात कही सूरत महानगर पालिका द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति तथा पीने के पानी की बर्बादी को रोकने के लिए पानी के हर कनेक्शन के साथ मीटर लगाने का प्रावधान है मीटर ना लगने के कारण ज्यादातर क्षेत्रों में पीने के शुद्ध पानी का दुर उपयोग किया जाता था या पानी लोक पौधों की सिंचाई तथा गाड़ियों की धुलाई में खर्च करते थे।

मनपा की तिजोरी पर सबसे ज्यादा खर्च वेतन भुगतान पर होगा

सूरत। महानगर पालिका को जितनी राजस्व की प्राप्ति होनी है उसमें से प्रोजेक्ट बनाने की बात तो दूर उससे उसके कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन का भुगतान भी नहीं हो पाएगा 2999 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति के सामने 3084 करोड रुपए का खर्च वेतन भुगतान पर होगा कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य भक्तों के साथ 1609 करोड रुपए की जरूरत होगी।

अंतर ढुंढों प्रतियोगिता के तहत उधना जोन द्वारा डीमोलेशन कर बनाई गई बिल्डींग

उधना जोन के जोनल ऑफीसर के भ्रष्टाचार की हद

सूरत। पांडेसरा-बमरोली रोड पर केशवनगर सोसायटी में सुरत महानगर पालिका के ओर से डिमोलिशन की कार्यवाही किया गया. जिसमें मनपा के अधिकारीयों ने सिर्फ नाम मात्र कागजों पर ही डिमोलिशन किया हैं इस तरह लगता हैं, जिसमें किसी भी डिमोलिशन के कार्यवाही में जोनल ऑफीसर की निगरानी में होता हैं, तो इस तरह से जो कार्यवाही किया गया वह किस अधिकारी के निगरानी में किया गया. सूत्रों के पास से मिली जानकारी अनुसार यह सिर्फ देखाने के लिये डिमोलिशन किया गया. जो सिर्फ दीवालो को गिराकर डिमोलिशन बता दिया ,लेकिन सच्चाई यह भी हैं की किसी आम आदमी का मकान भी बना रहा होता हैं, तो वहाँ पर ज़ोनल ऑफीसर किस अधिकारी या पदाधिकारियों के दबाव में कार्य करते हैं, कि मकान का स्लेब तोड़कर कार्यवाही करते हैं,अगर किसी बिल्डर के यह पर कार्यवाही होती हैं, तो सिर्फ दीवाल तोड़कर कार्यवाही करते हैं, जो यह फोटा के उपर से अस्पष्ट प्रतीत होता हैं की भ्रष्टाचार काफ़ी प्रगतिशील हो गया हैं। सुरत महानगर पालिका के अधिकारी और पदाधिकारियों किसी न किसी विवाद में होने के बावजूद किसी प्रकार की कार्यवाही किसी पर नही होती हैं, इस तरह से अनेक विवादों के चलते गुजरात में सुरत महानगर पालिका भ्रष्टाचार के मामले में भी काफ़ी प्रगतिशील हो गया हैं इस तरह के खबरें कई जगह पर देखा गया हैं,जिसमें सुरत महानगर पालिका के हर विभाग में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फेल गया हैं,की वह अब लोगों के सामने देखाई दे रहा हैं।

राजद्रोह मामले में हार्दिक पटेल कोर्ट में हाजिर

25 जनवरी को होगी सुनवाई

सूरत। मोटा वराछा कृष्णा रोसीडेंसी में पुलिस प्रशासन के विरुद्ध अनाब सनाब बोलने के मामले में हार्दिक पटेल सहित तीन आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चल रही कार्रवाई के तहत शुक्रवार को हार्दिक सहित तीन को कोर्ट में हाजिर किया गया। वचाव पक्ष के वकील जशवंत सिंह वाला ने बताया कि इस दौरान अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी का समय दिया है। पाटीदार आंदोलन के दौरान मोटा वराछा कृष्णा रेसीडेंसी में रहने वाले विपुल देसाई तथा चिराग देसाई के यहां जाकर पास के पूर्व कन्वीनर हार्दिक पटेल ने पुलिस के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रोयग किया था। इस गुनाह ने डीसीपी मकरंद चौहाण ने हार्दिक तथा उनके साथियों के विरुद्ध राजद्रोह का केस दायर किया था। इस केश में पूर्व पी.आई जे.एच दहिया ने हार्दिक तथा उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

तीसरे दिन भी गुजरात के नवसारी जिले में सबसे कम रहा तापमान

सूरत। समग्र दक्षणि गुजरात में पिछले 3 दिन से लगातार ठंडी का असर यथावत है राज्य में सबसे अधिक ठंडी नवसारी जिले में 7 डिग्री दर्ज की गई यह गिरावट अगले दो-तीन दिनों तक ऐसे ही बने रहने की अनुमान है सूरत मौसम विभाग सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार शुक्रवार की सुबह शहर का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 12. 4 डिग्री दर्ज किया गया हवा में नमी की मात्रा 73ज्ञ तथा हवा का दबाव 1018. 3 मिली बार दर्ज किया गया गत रोज की तुलना में शुक्रवार के तापमान में 1 से 1.5 डिग्री की कमी दर्ज की गई ।नवसारी मौसम विभाग सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार शुक्रवार को नवसारी का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री दर्ज किया गया समग्र राज्य में पिछले 3 दिनों से ठंडी का असर पहले की तरह बना हुआ है शुक्रवार को बलसाड में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया जो पिछले 3 दिनों से एक समान बना हुआ है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)